में बोल सकते हैं जिसके लिए कि संयुक्त राष्ट्र संगठन में दुभाषिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि प्रतिनिधिमंडल का कोई सदस्य हिन्दी में बोलना चाहे तो वह अनुवाद/भाषातर की व्यवस्था करके ऐसा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के दौरान इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जब कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में माननीय संसद सदस्य और जाने-माने गैर सरकारी व्यक्ति सदस्य की हैसियत से वहीं रहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संगठन में नई भाषा शुरू करने का खर्च उस सदस्य (देशों) पर पड़ता है जो उस भाषा का प्रस्ताव करता है और इस प्रकार की भाषा को शुरू करने पर अतिशय खर्च होगा।

विदेश मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

253. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा विभाग ने विदेश मंत्रालय, इसके दूतावासों और अन्य कार्यालयों को अपने अधिनियम तथा वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन से छूट दी है, यदि नहीं, तो अब तक मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की केवल एक ही बैठक किए जाने तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों में हिन्दी से संबंधित कोई कार्यक्रम लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय दूतावासों के पुस्तकालयों में हिन्दी की पुस्तकें तथा पत्रिकायें बहुत कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय संस्कृति को विदेशों में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन्) : (क) जी, नहीं। विदेश मंत्रालय और इसके कार्यालय राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुसरण करते हैं तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

इस मंत्रालय में हाल ही में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समिति के स्थान पर हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इसकी बैठक 14-2-86 को हुई थी। दूसरी बैठक जून में होनी थी किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यह बैठक नहीं बुलाई जा सकी। समिति की बैठक अब 22-8-86 को होगी।

विदेश स्थित हमारे राजदूतावास राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने की यथासंभव कोशिश करते हैं। तथापि, उनके कार्य का स्वरूप काफी भिन्न होता है क्योंकि उनके कार्य का अधिकांश भाग विदेशी सरकारों तथा विदेशियों से संबंधित होता है जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है।

(ख) और (ग) यह सही नहीं है कि भारतीय राजदूतावासों के पुस्तकालयों में हिन्दी की बहुत कम पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं। मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों से विदेश स्थित अपने मिशनों को नियमित रूप से हिन्दी की पुस्तकें भेज रहा है जिनमें भारतीय साहित्य, संस्कृति तथा धर्म से संबंधित विषयों की पुस्तकें भी शामिल होती हैं। मिशन उन विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों/व्यक्तिकों को भी हिन्दी पुस्तकें, फिल्में, रिकार्ड तथा अन्य सामग्री भेंट करते हैं जो भारतीय संस्कृति में रूचि रखते हैं। हमारे मिशन विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन भी करते हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर 'भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित समारोहों में भी भाग लेते हैं। इन समारोहों में विदेशियों की उपस्थिति का भी स्वागत किया जाता है।

वित्त मंत्रालय के कार्यालयों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

254. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों, विशेषकर बैंकों

बीमा निगमों एवं कस्टम आदि के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढवी) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय, और उसके अधीन अन्य संगठनों उसकी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं का कुल मिलाकर पालन किया जा रहा है । प्रोत्साहन, आदि देकर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जाते हैं ।

वस्त्र मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

255. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न तो वस्त्र मंत्रालय के मुख्यालय में और न ही एन टी सी. की मिलों में राजभाषा अधिनियम और इसके वार्षिक कार्यक्रमों का पालन किया जाता है;

(ख) एन.टी.सी. की मिलों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक मिल में राजभाषा का कितना-कितना प्रयोग हो रहा है; और

(ग) क्या यह सच है कि 10 जुलाई, 1986 से पहले कई वर्षों से हिन्दी सलाहकार समिति की एक भी बैठक नहीं बुलाई गई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने भी कोई कार्य नहीं किया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) मंत्रालय में तथा एन. टी.सी. की अधिकांश मिलों में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया जाता है । राजभाषा नीति की कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु सभी प्रयास किए जाते हैं ।

(ख) एन.टी.सी. की 107 राष्ट्रीकृत मिलें हैं । पश्चिम बंगाल स्थित एन टी. सी. (डब्ल्यू बी ए बी-आई) लि. कलकत्ता तथा एन.टी.सी. (टी.एन.पी.) लि., कोयम्बटूर के अन्तर्गत मिलों के सिवाय सभी एन.टी.सी. मिलों में राजभाषा का प्रयोग संतोषजनक समझा जाता है ।

(ग) जी नहीं । वस्त्र मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में 15-11-85 से बनाया गया है । उससे पहले वह वस्त्र विभाग के रूप में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन था और दोनों विभागों के लिए एक ही हिन्दी सलाहकार समित और राजभाषा कार्यान्वयन समिति थी । तत्कालीन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 26 अगस्त, 1985 को हुई थी । दोनों विभागों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पिछले वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से हुई ।

Discussions held between the Indian and Sri Lankan envoys to solve the ethnic issue

256. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in spite of efforts made by the Indian Government to solve the ethnic problem of Tamils, the Sri Lankan Government has failed to accept any proposal of the Indian Government;

(b) if so, what are the details of the discussions held between the envoys of both the Governments during May, June and July, 1986 and the outcome thereof; and

(c) what further steps are contemplated by Government to solve the issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) No, Sir.